









# भदोही संदेश

# बारिश ने बदली नगर व गांवों की सूरत



अखंड भारत संदेश

ज्ञानपुर। मंगलवार की रात से ही लगातार किसी समय रिमझिम तो किसी समय हो रही झाझ़िम बारिश ने नारीय क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण अचल तक की सूरत बदलकर रख दी है। जलजमाव की चीड़, नीसे से जहाँ लोगों के लिए आवागमन मुश्खिल हो गया तो कहीं मकान तो कहीं पेड़ धराशाई होने की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। ज्ञानपुर नगर के दुर्गापिंज रोड तिराहा व मोढ़ बाजार में धूने भर जमा हुए पानी से पानी निकासी को लेकर

व्यवस्था को लेकर किए जा रहे तमाम दावे की पोल खुल गई हैं।

करीब पक्खावे भर की भीषण उमस व गर्मी के बाद शुरू हुई बारिश से भले ही दिसानों के छहरे खिले हुए हैं, पानी को धान फसल के लिए लाभकारी माना जा रहा है।

वहीं दूसरी ओर बारिश से जहाँ जगह-जगह हो चुके जलजमाव से लोगों की फजीहत भी बढ़ चुकी है।

ज्ञानपुर नगर के दुर्गापिंज रोड तिराहा पर धूने भर जमा हुए पानी से जहाँ आवागमन में दिक्कत हुई तो वहीं पानी निकासी को लेकर

भी खुल गई। उठर ज्ञानपुर-गोपीनगर मार्ग पर स्थित पूरीपूर गांव के सभी प्रसंक पर भी विश्वालकाय पेड़ धराशाई हो जाने से आवागमन काफी दे तक अवश्य रहा।

मोढ़ प्रतिनिधि के अनुसार : लगातार हो रही बारिश से पूरा मोढ़ बाजार जील में बदल चुका है। पानी निकासी की व्यवस्था न होने से बारिश का सारा पानी सड़क पर जमा हुई है। इससे एक और जहाँ वाहन सवारों से लेकर पैदल राहीर तक परेशान हो रहे हैं, तो वहीं पानी निकासी को लेकर

व्यवस्था को लेकर किए जा रही तमाम व्यवस्था की पोल खुल गई है।

भदोही। बारिश ने कालीन नगरी की स्थित नारीय कर दी है। निकासी के अभाव में शहर के 80 फीसद क्षेत्रों में जलजमाव की स्थित है। कालीन कारखानों के साथ-साथ कई प्रतिलिङ्गों में भी पानी भर गया है। खुले मैदान पहले से ही जलमय हैं। इसके कारण बुनाई सहित अन्य कामकाज पूरी तरह ठप हो गए। इसके कारण एक तरफ जहाँ कामगारों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है, वहीं निर्यात की परेशान है। लोगों का कहना है कि मौसम का यहीं हाल रहा तो उपादन के साथ-साथ तैयारी भी प्रभावित होगी। रुक-रुक कर हो रही बारिश का सिलसिला दिन भर जारी रहा। उठर जलजमाव का हाल यह है कि स्टेशन रोड, पकड़ी तिराहा पिछले 36 घंटे से जलजमाव से मुक्त नहीं हो सके हैं। असिफ अंसारी के कारखानों में पानी भरने के कारण बुनाई कार्य ठप है। इसी तरह मुश्तक अंसारी के कंपनी में पानी भरा है। यहीं हाल घमाहुर, जलालुर नईबस्ती, आलमपुर सहित अन्य मोहल्लों में है।

बारिश के कालीन नगरी को किया पानी-पानी

ओजोन परत के हास पर वैज्ञानिकों ने जताई चिता

अखंड भारत संदेश

भदोही। विश्व ओजोन विवर के मौसम सर्वेक्षण विभाग प्रतिलिंग से वारिष्ठ वैज्ञानिक डा. सूरी सिवारेण्डन की ओर से आयोजित वैविनार में जुड़े विश्व भर के वैज्ञानिकों ने ओजोन परत के होते हास पर चिता जाहिर की। इस संकट से निवारने के लिए तैयार होते हास परवारण की नक्सान पटुचाने वाले समस्त कारकों प्लास्टिक, पालीथिन का प्रयोग कम करना होगा। पैध लागाकर उसे बचाना होगा। उहोंने बताया कि वैज्ञानिक अभियान दल अंटार्कटिका के सदस्य रामेश उपर्याय के अंतर्गत प्रतिलिंगी में पैदली बुर्जार की ओजोन डिस्ट्रिक्ट में जाकरी की स्थानीय स्थानों से डांगरा निकासी से आवागमन का लिए अवधारणा की। अपर्याप्त सर्वेक्षण के लिए हरितिम संवर्धन के लिए प्रेरित किया। ओजोन के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि गर्मी के माह में ओजोन का हास अपेक्षाकृत तो तो से होता है। हास की दर प्रति दशक उत्तरी ओर दक्षिणी मध्य अक्षांश में लगभग पांच फीसद है।

जनपद के नेवाडा निवासी भारतीय वैज्ञानिक अभियान दल अंटार्कटिका के सिलसिला दिन भर जारी रहा। उठर जलजमाव का हाल यह है कि स्टेशन रोड, पकड़ी तिराहा पिछले 36 घंटे से जलजमाव से मुक्त नहीं हो सके हैं। असिफ अंसारी के कारखानों में पानी भरने के कारण बुनाई कार्य ठप है। इसी तरह मुश्तक अंसारी के कंपनी में पानी भरा है। यहीं हाल घमाहुर, जलालुर नईबस्ती, आलमपुर सहित अन्य मोहल्लों में है।

जनपद

भदोही। विश्व ओजोन विवर के मौसम सर्वेक्षण विभाग प्रतिलिंग से वारिष्ठ वैज्ञानिक डा. विजय कुमार सोनी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. परवीर जी ने वैविनार से ज़इक अपने शोध कार्यों से सभी को अवगत कराया।

न्यायालय के आदेश

पर मुकदमा दर्ज

भदोही। गोपीगंज थाना क्षेत्र के जोगियां गांव निवासी संजय

सिंह की आचिक निवासी जानकारी दी। पर्यावरण सर्वेक्षण

के लिए हरितिम संवर्धन के लिए प्रेरित किया। ओजोन के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि गर्मी के माह में ओजोन का हास अपेक्षाकृत तो तो से होता है। हास की दर प्रति दशक उत्तरी ओर दक्षिणी मध्य अक्षांश में लगभग पांच फीसद है।

बारिश के दौरान अचानक मकान का एक हिस्सा पिर पड़ा। मलवे में दबने से अलमारी, गैरू चूहा, इंडस्ट्रेशन, सूक्ष्म सहित गुह्यस्थी के अन्य सामान दबकर नष्ट हो गए। बुधवार की शाम तो रही

जाएगा। उहोंने जानकारी दी

अखंड भारत संदेश

भदोही। सामुदायिक स्वास्थ्य

केंद्र सुरियावां में गुरुवार को

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य

कार्यक्रम के तहत विकित्सा एवं

जागरूकता शिविर में 15 मरीजों

को उपचार किया गया। साथ लोगों को मानसिक तनाव को लेकर जागरूक किया गया। बताया गया कि लोगों को हमेशा तनाव ही मानसिक रोग का मुख्य कारण होता है। ऐसे में लोगों को हमेशा तनाव से दूर रहना चाहिए।

जिला पंचायत सदस्य

चंद्रशूषण उर्प पूपु प्रियाणी ने शिविर

का शुभारंभ किया। कहा कि इस

तरह के शिविर से मरीजों को जांच से लेकर उपचार तक की

सुविधा पूर्ण असामी के साथ मिल जाती है। प्रभारी निकित्सा की अधीक्षक

तिवारी का मकान धराशाई हो गया।

इससे जहाँ हजारी रुपये का सामान

दबकर नष्ट हो गया तो मलवे की जद

में आने से वह गंभीर रूप से घायल

भी हो गए। बुधवार की शाम तो रही

समस्या से छुकरा मिल जाता

है। शिविर में डा. आनंद स्वरूप,

रामप्रकाश, ईश्वरचंद्र रम्पा, किरन

यादव, प्रेमा देवी, रामशरण,

राजनीश आदि थे।

बारिश के दौरान अचानक मकान का

एक हिस्सा पिर पड़ा। मलवे में दबने

से अलमारी, गैरू चूहा, इंडस्ट्रेशन,

सूक्ष्म सहित गुह्यस्थी के अन्य सामान

दबकर नष्ट हो गए।

समस्या से छुकरा मिल जाता

है। शिविर में डा. आनंद स्वरूप,

रामप्रकाश, ईश्वरचंद्र रम्पा, किरन

यादव, प्रेमा देवी, रामशरण,

राजनीश आदि थे।

किसानों के नलकूप व आम जनता के घरेलू

साकिपा बिजली बिल माफ करे सरकार-अजय साकिपा बिजली बिल माफ करे सरकार-अदेश

# सम्पादकीय

# तेजी से बढ़ती असमानता

क्रेडिट सुईस की ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2018 में तो कहा गया था कि देश की सबसे अमीर एक फीसदी आबादी के पास 51.5 फीसदी संपत्ति इकट्ठा हो गई है। ऐसी अलग-अलग रिपोर्टों में प्रतिशत का थोड़ा-बहुत अंतर कभी-कभार दिखता है तो उसकी एक वजह यह होती है कि उनमें संपत्ति की गणना के पैमाने अलग-अलग होते हैं। नैशनल सैंपल सर्वे द्वारा करवाए गए औलैंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे 2019 की रिपोर्ट ने एक बार फिर देश में लगातार बढ़ती गैर-बराबरी की ओर ध्यान खींचा है। रिपोर्ट के मुताबिक, देश की कुल संपत्ति का आधे से अधिक हिस्सा ऊपर की दस फीसदी आबादी के हाथों में सिमट गया है। निचले हिस्से की 50 फीसदी आबादी के पास महज दस फीसदी संपत्ति है। गांवों के मुकाबले शहरों में यह विभाजन और तीखा नजर आता है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अमीर दस फीसदी लोगों के पास 50.8 फीसदी संपत्ति है वहाँ शहरी क्षेत्रों में यह 55.7 प्रतिशत पाया गया है। इस विस्तृत सर्वे रिपोर्ट के अलग-अलग कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिन पर बारीकी से विचार होना चाहिए, लेकिन एक तथ्य स्पष्ट है कि विकास की प्रक्रिया जिन इलाकों में ज्यादा तेज रही, वहाँ असमानता का अनुपात भी ज्यादा है। इस तथ्य के अपने गहरे निहितार्थ भले हों, लेकिन यह अपने आप में कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी समय-समय पर आने वाली अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में यह तथ्य उजागर होता रहा है कि भारत में विकास की गति तेज होने के बाद भी पिछले ढाई-तीन दशकों में विषमता में तेज बढ़ती हुई है।

क्रेडिट सुर्फ़स की ग्लोबल वेल्यू रिपोर्ट 2018 में तो कहा गया था कि देश की सबसे अमीर एक फीसदी आबादी के पास 51.5 फीसदी संपत्ति इकट्ठा हो गई है। ऐसी अलग-अलग रिपोर्टों में प्रतिशत का थोड़ा-बहुत अंतर कभी-कभार दिखता है तो उसकी एक वजह यह होती है कि उनमें संपत्ति की गणना के पैमाने अलग-अलग होते हैं। लेकिन इस तथ्य की पुष्टि इन तमाम रिपोर्टों से होती है कि भारतीय समाज में विषमता सुरक्षा के मुद्दों की तरह लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे यह रुझान अपने देश तक सीमित नहीं है। किसी भी समाज में अगर तेजी से समृद्धि आती है तो यह संभावना रहती है कि शुरू में संपत्ति आबादी के कुछ खास हिस्सों के हाथों में आए, जिससे विषमता बढ़ी हुई दिखने लगे। अपेक्षा यह रहती है कि बाट के दौर में यह धीरे-धीरे समाज के अन्य तबकों तक पहुंच कर उनके जीवन स्तर को भी ऊंचा करेगी। इसी बिंदु पर योजनाओं की भूमिका अहम होती है। इस बात का ध्यान रखना होता है कि अपनी स्वाधाविक गति में यह समृद्धि समाज के अन्य तबकों तक पहुंच रही है या नहीं। अगर नहीं पहुंचती है तो यह देखना होता है कि उसकी गति को बाधित करने वाले कारक कौन से हैं और उन्हें दूर करने के क्या इंतजाम हो सकते हैं। एनएसएस के ताजा आंकड़े बताते हैं कि अपने देश में सरकार को ऐसे इंतजामों पर खास ध्यान देने की जरूरत है।

# क्यों अनजान चेहरों को सीएम बनाती है बीजेपी

## नौलाजन मुखोपाध्याय

ગુજરાત મેં અચાનક વિજય રૂપાણી કો હટાકર ભૂદ્ર પટેલ કો મુખ્યમંત્રી બનાને કે ફેસલે પર પ્રથાનમંત્રી નરેંદ્ર મોદી કી સ્પષ્ટ છાપ દિખતી હૈ। મોદી 2001 મેં ગુજરાત કે મુખ્યમંત્રી બને થે। ઉસકે બાદ ઉન્હોને પહલે રાજ્ય કી સરકાર ચલાઈ ઔર અબ દેશ કી સરકાર ચલા રહે હૈને। ઇસ દૌરાન બીજેપી મેં કર્ડ રણનીતિક ફેસલે ઉન્કે કહને પર હુએ। એસા નહીં કિ ઇન ફેસલોને પર અમલ કરને સે પહલે પાર્ટી મેં ચર્ચા નહીં હોતી, લેકિન યહ ભી સચ હૈ કિ એકાધ મામલોનો કો છોડ દેં તો જ્યાદાતર મેં મોદી હી આખિરી ફેસલા કરેટે હૈને। ગુજરાત મેં ભી યહી હુઆ, લેકિન રૂપાણી કો હટાકર પટેલ કો મુખ્યમંત્રી બનાને કા પ્રયોગ સફળ હોતા હૈ યા નહીં, યહ કર્ડ બાતોં સે તય હોગા। ઇસ પર જહાં વિપક્ષી દલોની ચુનાવીતિયોની કા અસર હોગા, વહીં બીજેપી કે અંદર સે ઊઠને વાલે વિરોધ કા ભૌ પ્રભાવ પડેગા। ગુજરાત કે ઇસ મામલે કો અલગ-થલગ કરકે દેખના ઠીક નહીં હોગા। રૂપાણી કો હટાકર પટેલ કો મુખ્યમંત્રી બનાને કા ફેસલા કર્ડ એસે કદમોની કી કડી હૈ, જિન્હેં હાલ મેં પ્રથાનમંત્રી ને શુરૂ કિયા હૈ। ઇસસે પહલે ઉત્તરાંખંડ ઔર કર્નાટક મેં મુખ્યમંત્રી બદલે ગણ। કેંદ્ર સરકાર મેં કર્ઝ નહીં મંત્રી બનાએ ગણ। કુંઠ કો બાહર ભી કિયા ગયા। ઇનકા મકસદ ઇસ સાલ કી શુરૂઆત મેં કોરોના કી દૂસરી લહર કે દૌરાન લચર વ્યવસ્થા સે ઉપર્જી નારાજગી કો દૂર કરના થા। કેંદ્રીય મંત્રીપરિષદ મેં બદલાવ કે જરિયે લોગોનો સંદેશ દિયા ગયા કિ દોષિયોની કો સરકાર ને સજા દે દી હૈ। સ્વાસ્થ્ય મંત્રી હર્ષવર્ધન કો ઇસીલિએ હટાયા ગયા। ઇસ બીચ, પ્રથાનમંત્રી કી લોકપ્રિયતા વિપક્ષ કે દૂસરે નેતાઓને સે ઊપર બની હુઈ હૈ, લેકિન મોદી કો ઇસકા અહસસ ભી હોગા કિ લોગોની બીચ ઉનકી સાખ પહલે જૈસી નહીં રહી। સચ યહ ભી હૈ કિ ઉનકે

**मौसमी धर्मनिरपेक्षता के माहिर नीतीश कुमार..  
बख्तियारपुर, अब्बा जान और जमा खान से समझिए**

आलोक कुमार

नीतीश कुमार पिछले दिनों तमतमा गए। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग हो रही है। इस पर उनका क्या कहना है। भड़के नीतीश ने कहा, हम जहाँ जन्मे हैं उहरे का नाम बदलेगा, बिना मतलब की बात करते हैं। फालतू बात है। फिर कुछ दिनों बाद उनकी पार्टी जनता दल (यूनाईटेड) के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की बारी थी। उनसे पत्रकारों ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बाबाजान वाले बयान पर प्रतिक्रिया ली। उन्होंने भर्त्सना तो नहीं की लेकिन असहमति ऐसे जताई - किसी भी राजनीतिक दल के नेता को संयमित भाषा में अपनी बात रखनी चाहिए। देश सबका है। हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सभी का है। ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे देश को नुकसान हो। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव है। बिहार में पार्टी कमज़ोर है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) हावी होती जा रही है। इसलिए सेक्युलर दिखाने का टाइम है। नीतीश कुमार ने नया-नया ताज दिया है तो ललन सिंह जेडीयू विस्तार करने चले हैं। अगस्त में ही उन्होंने साफ कर दिया कि अगर बीजेपी ने सम्मानजनक सीटें नहीं दी तो उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। वो बिहार में मिले सम्मान के नतीजे को भूल गए। सीट शेयरिंग में 122 सीटें मिली। सात जीतन राम माझी को दी। 115 पर लड़े और 72 सीटें पर

मोदी सिर्फ सबका साथ सबका विकास  
की बात करते हैं या कुछ करते भी हैं

**नीरज कुमार दुबे**

कुछ खास हिस्सों के हाथों में आए, जिससे विषमता बढ़ी हुई दिखने लगे। अपेक्षा यह रहती है कि बाद के दौर में यह धीरे-धीरे समाज के अन्य तबकों तक पहुंच कर उनके जीवन स्तर को भी ऊंचा करेगी। इसी बिंदु पर योजनाओं की भूमिका अहम हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना होता है कि अपनी स्वाभाविक गति में यह समुद्धि समाज के अन्य तबकों तक पहुंच रही है या नहीं। अगर नहीं पहुंचती है तो यह देखना होता है कि उसकी गति को बाधित करने वाले कारक कौन से हैं और उन्हें दूर करने के क्या इंतजाम हो सकते हैं। एनएसएस के ताजा आंकड़े बताते हैं कि अपने देश में सरकार को ऐसे इंतजामों पर खास ध्यान देने की जरूरत है।

भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने देश को जो बड़े नारे यह फिर कहिये सूत्रवाक्य दिये वह हैं- एक भारत, श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। नरेंद्र मोदी ने अपने लिए बड़े घर बनाने की जगह प्रधानमंत्री आगास योजना के तहत रिकॉर्ड संख्या में जरूरतमंदों के सिर पर छत प्रदान की। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपनी निर्वाचन क्षेत्र या अपने गृहराज्य की चिंता करने की बजाय देश का समान रूप से विकास की ऐसी ढोरों परियोजनाएं प्रदान कीं जिससे नये भारत का निर्माण चारों ओर होता दिख रहा है।



नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति और जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 क हटाने के बादे भारत में बरसों से सुने जाते थे लेकिन यह सब साकामोदी सरकार के कार्यकाल में ही हुए। यही वह सरकार है जिसने उद्योगों को मजबूती प्रदान करने के लिए उन्हें तमाम तरह की रियाय प्रदान कीं, उद्योगों की स्थापना संबंधी प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया, मंजुरियां प्रदान करने की प्रक्रिया को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया, युगाओं को रोजगार पाने की जद्दोजहद में जुटने की बजाय उन रोजगार प्रदान करने लायक स्थिति में पहुंचाने के लिए तमाम योजनाओं को पेश किया, कोरोना के कहर से देश को बचाने के लिए भारत वैक्सीन के निर्माण को प्रोत्साहित भी किया तथा दुनिया में सबसे ज्यादा और तीव्र गति से वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया, संकेत के समय महीनों तक गरीब जनता को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया। यही नहीं ओलम्पिक और पैरालम्पिक खेलों के सभी पदक विजेताओं और प्रतिभागी खिलाड़ियों का हौसला प्रधानमंत्री ने निजी रूप से बढ़ाया। यह सही है कि मोदी की छवि हिंदूवादी नेता की रही है लेकिन उन्होंने सदैव दूसरे धर्मों को भी समान रूप से सम्मान दिया भोलेनाथ के भक्त और काशी के जनसेवक मोदी ने रामनगरी अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण कार्य का शुभारम्भ कर हिन्दुस्तान की जनत का सैकड़ों वर्षों पुराना सपना साकार कर दिया तो मोदी सरकार दे कार्यकाल में ही अल्पसंख्यक मंत्रालय ने मुस्लिमों के लिए इतनी योजना पेश की कि आज यह वर्ग पहले की अपेक्षा ज्यादा पढ़ा-लिखा औं

चलता है कि अंदरखाने नेता विरोध जताने लगे हैं। पार्टी पहले किसी व्यक्ति या किसी थड़े की मांगों पर ध्यान नहीं देती थी। नरेंद्र मोदी के लोकप्रियता सब पर भारी पड़ती थी क्योंकि चुनावों में उन्हीं के दम पर जीत मिल रही थी। इधर, बीजेपी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के बीच हाँ राज्य में पहले जैसा तालमेल नहीं दिख रहा। 2014 में पार्टी के अंदर मोदी ने जिस ढांचे को चुना, वह वाजपेयी-आडवाणी युग के संघीय ढांचे से बिल्कुल अलग था। पहले राज्यों में नेताओं को उभरने का मौका दिया जाता था। उसे अच्छा माना जाता था। इसी नीति के कारण मोदी का राष्ट्रीय राजनीति में उभार हुआ, लेकिन 2014 के बाद बीजेपी में हाई कमाल कल्चर का दबदबा बढ़ा। अजीब बात है कि यह नेहरू के बाद के कांग्रेस युद्ध की याद दिलाता है। इस दौर में राजस्थान में वसंधरा राजे और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बने तो रहे, लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत का हो गई। मोदी ने उसी अंदाज में नए मुख्यमंत्री चुने, जैसे इंदिरा गांधी चुनते थीं। उन लोगों को राज्यों में शीर्ष पद पर बिठाया गया, जिनका मामूल जनाधार था और जो केंद्रीय नेतृत्व के सामने कोई चुनौती पेश नहीं कर सकते थे। इसमें 2017 में एक बदलाव आया, जब योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि वह इस पद के उम्मीदवार तब नहीं थे। इसमें संघ परिवार के अंदर के राजनीतिक समीकरणों की भूमिका थी। यह बात और है कि 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इसमें मोदी को फायदा ही हुआ। इसमें दिक्कत यह आई कि दूसरों की तुलना में आदित्यनाथ स्वायत्त मुख्यमंत्री साबित हुए। यह बात पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को पसंद नहीं आई। असम में भी 'निचले स्तर से दबाव' के कारण हिमाचल बिस्व सरमा को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। यहां भी मोदी का राज्यों के लिए पिछला मॉडल नहीं चला। हालांकि, अब गुजरात में जिस तरह से मुख्यमंत्री को बदला गया है, उससे संकेत मिलता है कि प्रदेश स्तर पर मोदी की पकड़ कमज़ोर नहीं हुई है।

संपन्न नजर आ रहा है। मोदी ने इस देश में बरसों से चल रही तुष्टिकरण की राजनीति को तो समाप्त किया ही मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक के अभिशाप से भी मुक्ति दिलाई। आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन हो या फिर रक्षा बंधन या भैया दूज का त्योहार, मुस्लिम महिलाएं मोदी को भाई के रूप में राखी भेजती हैं, तिलक भेजती हैं। प्रधानमंत्री स्वयं कई बार अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबुद्ध लोगों से बात कर उनकी समस्याएं हल करने की दिशा में कदम उठा चुके हैं। यही कारण है कि देश में लोकसभा और विधानसभा की कई ऐसी सीटें हैं जो अल्पसंख्यक बहुल होने के बावजूद भाजपा के पास हैं। यह दर्शाता है कि मुस्लिमों को वोट बैंक के रूप में देखने वालों के दिन अब लद चुके हैं।

इस देश में दलितों और पिछड़ी को भी सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखा जाता था लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से उनकी सामाजिक और आर्थिक दशा में बड़े बदलाव आये हैं। सबको याद होगा कि प्रयागराज के कुंभ मेले में स्वच्छता कर्मियों के पैर खुद प्रधानमंत्री ने धोये थे और उन्हें सम्मानित किया था। आज पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने का काम जितना नरेंद्र मोदी ने किया है उन्हांना आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। यही नहीं गांवों और किसानों की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए ना सिर्फ अनेकों योजनाएं पेश कीं बल्कि उनके क्रियान्वयन पर खुद निगाह भी रखी। गरीब किसानों की मदद के बादे तो पहले भी किये जाते थे लेकिन नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान योजना के जरिये ना सिर्फ उनकी आर्थिक मदद की बल्कि तमाम तरह की फसलों का एमएसपी समय-समय पर बढ़ाकर उन्हें और सशक्त भी किया। बहरहाल, आज पूरे विश्व भर का जो माहौल है उसमें जनता से मिले भारी बहुमत की ताकत रखने वाला नेता ही देश के हितों से जड़े मुद्दों को वैश्विक मंचों पर पूरी ताकत के साथ उठा सकता है। मोदी राष्ट्र हित में फैसले लेने के लिए राजनीतिक नुकसान की परवाह नहीं करते इसलिए वह देश के लिए कई साहसिक निर्णय ले पाये हैं। प्रतिदिन 24 में से 18 घंटे काम करने वाले भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के लिए देश सेवा ही सबकुछ है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद तक पहुँचने का उनका सफर हमारे लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है जहाँ सामान्य परिवार से जुड़ा व्यक्ति भी शीर्ष पद तक पहुँच सकता है।

**ਬਾਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਡੀ, ਅਥਵਾ  
ਕਵਾਡ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ**

सीमा सिरोही

आने वाले क्वाड (अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया) शिखर सम्मेलन पर सबकी नजरें टिकी हैं। आशा है कि इस बार वहां कुछ स्पष्ट जवाब और दृढ़ प्रतिबद्धताओं की झलक मिले और बार-बार दोहराई जाने वाली घोषणाओं से बात आगे बढ़े। इस सम्मेलन की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कर रहे हैं, जो कोविड-19 और अफगानिस्तान जैसी चुनौतियों से तो धिर ही हैं, उनकी अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी में दरार अलग पड़ रही है। ऐसे में उनकी टीम क्वाड के अंजेंडे के प्रति अपना कमिटमेंट दिखाना चाहती है, यह देखने वाली बात होगी।

इस बार क्वाड के चारों नेता वैक्सीन डिलिवरी, नई तकनीक, जलवायु परिवर्तन की पहल आदि के साथ-साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन पर भी चर्चा करेंगे। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मदद से तालिबान दुनिया को हर संभव तरीके से परेशान कर रहे हैं। चाहे आतंकवादियों से भरी सरकार बनाने की बात हो या औरतों को बुर्का पहनाने की, वे कोई कसर बाकी नहीं रख रहे। पत्रकारों और महिलाओं को कोडे मारने के विडियो इतनी ज्यादा संख्या में हैं कि नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। जाहिर है, तालिबान के राज में अफगानिस्तान का भविष्य कैसा होगा, यह समझना खास मुश्किल नहीं है।

अफगानिस्तान से शर्मनाक वापसी के चलते बाइडन की विशेष जिम्मेदारी बनती है। क्वाड के बाकी नेताओं- नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन और जापान के योशिहिदे सुगा- के साथ मिलकर बाइडन को अफगानिस्तान पर साफ सिग्नल देना होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि वे प्रतिबंधों को बनाए रखेंगे, मान्यता देने की जल्दबाजी नहीं करेंगे और फेंडस पर लगी रोक जारी रखेंगे। अफगानिस्तान की 'इन्क्लूसिव' सरकार का चेहरा साफ हो जाने के बाद रूस और चीन भी अपनी शुरुआती उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान तो इतना परेशान हुआ कि खुलकर सामने आने से खुद को नहीं रोक सका। तालिबान-आईएसआईएस के हाथों अमेरिका को मिली हार की शुरुआती खुशी धूंधली पड़ने लगी है। रूस तो मध्य एशिया में कट्टरता का दबदबा बढ़ने की आशंका से साफ तौर पर चिंतित है। चीन भी असमंजस में है कि पाकिस्तान वाकई वहाँ के हालात संभाल पाएगा या नहीं। अमेरिका हार गया है इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि कोई जीता नहीं है।

है। तालिबान को छोड़कर सभी नुकसान में ही हैं। अफगानिस्तान पर भारत और रूस भी अलग से बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने इस मसले पर एक साझा नजरिया बना लिया है। ईरान के नए विदेश मंत्री हुसैन अब्दुल्लाहियन इसी हफ्ते ताजिकिस्तान के दुश्मांबे में एस जयशंकर से मिलेंग। क्या अफगानिस्तान पर त्रिपक्षीय समझ बन सकती है 11 अगस्त को कर्तव्र में पाकिस्तान,

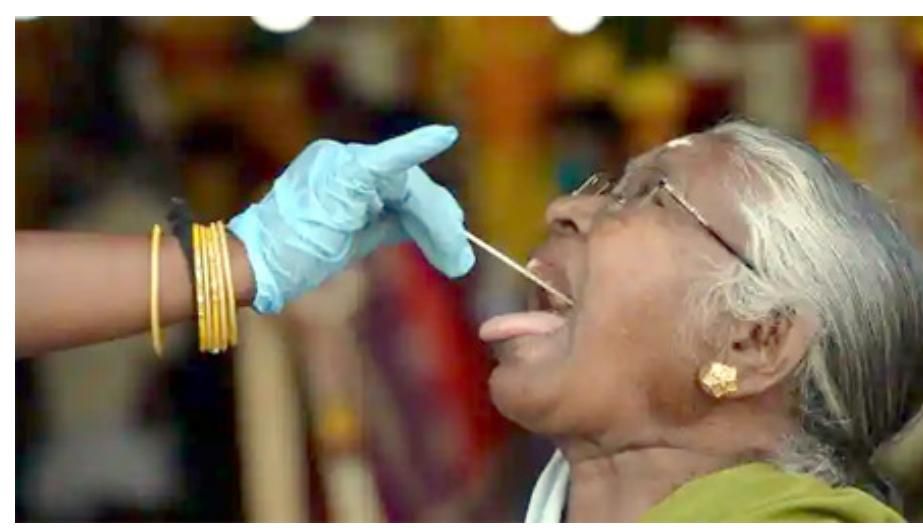
पर त्रिपक्षीय समझ बन सकता है 11 अगस्त का कवर म पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के 'ट्रोइका टॉक' से भारत को बाहर रखने वाले रूस के विशेष दूत जमीर काबुलोव की बोलती बंद है। उनके प्रयासों के मनमाफिक नतीजे नहीं आए। बदले हालात में भारत का ध्यान रूस पर है। यही समय है कि बाइडन को भी इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। चीन की तुलना में रूस को साथ लेना कहीं अधिक आसान है। पिछले हफ्ते बाइडन ने शी जिनपिंग को फोन किया था। 90 मिनट की बातचीत हुई, लेकिन इसके नतीजे क्या होंगे, यह साफ नहीं है। बाइडन की निजी कूटनीति से शी पर बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। जॉन केरी जब पिछले हफ्ते चीन में थे तो चीनियों ने उनका अपमान किया। केवल एक जूनियर अधिकारी केरी से मिलने गया। अमेरिका और चीन की मार्च 18-19 को अलास्का में हुई पहली मीटिंग सहित अब तक की सारी मीटिंगें बेकार ही गई हैं। चीन के साथ चल रहे विवादों में से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को अलग करने की बाइडन की रणनीति काम नहीं आ रही। इस पर फिर से सोचने की जरूरत है। चीनी अमेरिकियों को बैडज़ज़त करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन डील के लिए बेताब दिखता है, जबकि चीनी उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी में पड़ती दरारों के मजे ले रहे हैं। यह सब देखते हुए क्वाड को इंडो-पैसिफिक को मुक्त बनाए रखने की अपनी खालिश के बारे में थोड़ा अलग तरीके से सोचना चाहिए। टीके तो जरूरी हैं, पर गायरस की उत्पत्ति के सवाल पर पूरी पारदर्शिता के साथ चीन की जिम्मेदारी तय करना भी उतना ही जरूरी है।



# देश विदेश संदेश

चेन्नई: एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने पकड़ी विदेशी मकड़ियों की खेप

नई दिल्ली (एजेंसी)। चेन्नई एयरपोर्ट पर कर्स्टम विभाग की टीम ने विदेशी से लाइ गैरुल्भ मकड़ियों की एक बड़ी खेप बरामद किया है। अनी सूना के आधार पर चेन्नई एयर कर्स्टम की टीम ने एक पोर्सल पासेल की जांच की और इसी दौरान टीम को यह सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि यह पासेल पोलेंड से फॉरेन पोस्ट ऑफिस तक पहुंचा था। यह पासेल अंग्रेज प्रदेश के एक गाले एक युवक गुरुका के पाते पर भेजा था। यह पासेल को खेले पर थमेकोलं का एक बक्सा मिला। इस बक्से को कॉटन और सिल्वर फॉयल से अच्छी तरह लेपन किया था। जांच के दौरान बक्से के अंदर जिदा मकड़े नज़र आए। एनिमल व्हारान्टाइन अधिकारियों ने इस मकड़े की जांच की और कहा कि जिस देश में इस प्रजाति वाले रहा तब जाते हैं तब देश में इस पासेल को भेज दिया जाना चाहिए। अधिकारियों ने कहा कि इस्पोर्ट करना अवैध है और पासेल पर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रैड का लाइसेंस भी नहीं है।



## कोरोना से निपटने को सरकार ने बताए 4 मंत्र, केरल समेत 6 राज्यों को बताया चिंता की वजह

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों पर पूरी तरह से विराम तो नहीं लग पाया है लेकिन, गिरावट जरूर देखने को मिला है। इस बीच केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 4 उपाय बताए हैं। इसके साथ-साथ सरकार ने केरल समेत 6 राज्यों के मौजूदा हालात को चिंता जनक बताया है। ये वो राज्य हैं जहां पर कोरोना कभी उपर तो कभी नीचे हो रहा है। आईसीएमआर के डीजी बॉलाम भार्गव ने जिन चार यागों को बताया है उसमें पहला उपाय है वैस्तीन की स्वीकृति, दूसरा है कोविड उपयुक्त व्यवहार को ध्यान में रखना और लीसारा जिम्मेदारी से यात्रा करना वो भी अग्र दौरानी हो तब तक में इस प्रजाति वाले रहा पासेल को भेज दिया जाना चाहिए। अधिकारियों ने कहा कि इस्पोर्ट करना अवैध है और पासेल पर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रैड का लाइसेंस भी नहीं है।

है। इसके अलावा पांच राज्य मिज़ोराम, आधा प्रदेश, कर्नाटक, और आखिरी और चौथा उपाय है किसी उत्तर को जिम्मेदारी से मनाना। सरकार ने बताया कि देश में कोरोना वायरस के रिपोर्ट किए गए मामले में से लगभग 68 प्रतिशत केरल में भी रहे।